



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, २२ मई, २०२१

ज्येष्ठ १, १९४३ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग—४

संख्या १२१२ ख/छ:-पु-४-२१-१३(३९)-बी-२०२१

लखनऊ, २२ मई, २०२१

अधिसूचना

प०आ०—१५६

चूंकि राज्यपाल की यह राय है कि जिला कारागार, चित्रकूट में दिनांक १४ मई २०२१ को बन्दियों १—मुकीम उर्फ काला, पुत्र मुस्तकीम, २—मेराज अहमद, पुत्र जलालुद्दीन, ३—अंशू दीक्षित उर्फ सुमित, पुत्र जगदीश की हुई मृत्यु की सम्पूर्ण घटना से संबंधित लोक महत्व के विषय की जाँच आयोजित करना आवश्यक है।

२—अतएव, अब, जाँच आयोग अधिनियम, १९५२ (अधिनियम संख्या ६० सन् १९५२) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री शशि कान्त को एकल सदस्यीय जाँच आयोग, जिसका मुख्यालय चित्रकूट में होगा, के रूप में नियुक्त करती है।

३—चूंकि राज्यपाल की राय है कि, की जाने वाली जाँच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है। अतः राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन यह निदेश देती है कि उक्त धारा ५ की उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे।

४—आयोग, इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से ०२ मास की अवधि के भीतर अपनी जाँच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन, शासन की ओर से किया जायेगा।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1212 kha/chha-pu-4-21-13(39)-B-2021, dated May 22, 2021:

No. 1212 kha/chha-pu-4-21-13(39)-B-2021

Dated Lucknow, May 22, 2021

WHEREAS the Governor is of the opinion that it is necessary to hold an inquiry with regard to matter of public importance regarding the entire episode relating to death of prisoners 1. Mukeem *Alias* Kala, S/o Mustkeem, 2. Meraj Ahmad, S/o Jalaluddin, 3. Anshu Dixit *Alias* Sumit, S/o Jagdeesh on May 14, 2021 in District Jail, Chitrakoot about the death of the aforesaid prisoners.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Act no. 60 of 1952), the Governor is pleased to appoint Justice Shri Shashi Kant (*Retd.*), High Court, Allahabad as a single member Commission of Inquiry with Headquarters at Chitrakoot.

3. The Governor, being of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, it is necessary so to do, is further pleased to direct under sub-section (1) of section 5 of the said Act, that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

4. The Commission shall complete the inquiry within a period of two months from the date of the issue of this notification. Any change in its tenure shall be at the behest of the Government.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.